

● **UP :** आकांक्षा दुबे केस में आरोपी समर सिंह को पुलिस ने हूंद निकाला, मिल सकते हैं इन अनसुलझे सवालों के जवाब

● **Amritpal:** तलवंडी साबो में आज सटेंडर कर्टेगा अमृतपाल! पंजाब पुलिस तैयार, 14 अप्रैल तक कमियों की छुट्टियां रद्द

● **Delhi:** मनीष सिंसोदिया ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा- 'भारत की प्रगति के लिए एक शिक्षित पीएम होना जरूरी'

● **Corona Alert:** देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 6050 केस आए; बीते दिन से 13 फीसदी बढ़े गए केस

● **Tuni Agnikand:** चार मंजिला घर में आग लगने से जिंदा जल गए चार मासूम, मौके पर पहुंची डीएम सहित अधिकारियों की टीम



www.dgr.co.in | www.detectivegroupreport.com

वर्ष : 8 अंक : 267

इंडौर, सुक्रवात 07 अप्रैल, 2023

पेज : 8, मूल्य : 2 रुपए

निलंबित जेल अधीक्षक के लॉकर में मिला

3 किलो सोना

● **डिटैक्टिव ग्रुप रिपोर्ट**

उज्जैन। उज्जैन की केंद्रीय जेल भेरवगढ़ में करोड़ों के गबन की आरोपी पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज का बैंक लॉकर खुलवाया गया। गुरुवार रात तक लॉकर की सर्चिंग चलती रही। इसमें करीब तीन किलो सोना, डायमंड ज्वेलरी, एफडी और प्रॉपर्टी संबंधी कई दस्तावेज पुलिस को मिले हैं। गबन के मामले में ये बड़ी रिकवरी बताई जा रही है। डूधर, एसआईटी में अभियोजन अधिकारियों को भी शामिल कर लिया गया है।

प्रॉपर्टी के दस्तावेज और एफडी भी मिली 100 कर्मचारियों के PF के गबन का आरोप

उषा राज ने पुलिस को गुप्तज्ञाप में अब तक कुछ खास जानकारी नहीं दी। मामले में डीपीएफ के अलावा पे-मिल खातिर कई तरह की मुद्रकती सामान आई। इस बीच इन्कवरी को लेकर पुलिस को संकेत ने उषा राज के लॉकर खोलने की अनुमति दे दी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भी पुलिस को कई घंटे बैंक में जवाबदर करनी पड़ी, जब जाकर रोटी नगर को बैंक अंदर ड्रॉइंग के लॉकर खुलवाया जा सका। उषा राज की 8 लॉकर को रिमांड खान से ली रही है। पुलिस शुक्रवार को लॉकर में मिले ज्वेलरी दस्तावेज का खुलासा कर सकती है।

● **एसआईटी में इन्हें भी किया शामिल**

उप संचालक अभिषेक राव, सफात प्यार, एडीओ वीकेएस कृष्ण और उमेशसिंह सेनर को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। एस्पी सचिन शर्मा के निदेश के बाद केस जापरी तैयार करने में अभिषेक राव मजबूत संघ में कोई कमी न रह जाए, इस्तीफा अथवा एसआईटी में अभिषेक राव अतिक्रमण भी हर पल को निधि अनुसर कारणी प्रक्रिया से मजबूत करणें।

जेल प्रहरी देवेंद्र रायसेन से गिरफ्तार

कोरी से जर्बतब सफूरी के आरोप में बंगार जेल प्रहरी देवेंद्र रायसेन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह रायसेन में बंदन के रातों रात हुए हुए था। सीक्रेटरी अमित शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया कि कोरी में पंचा करने पर जेल प्रहरी प ज जर्बतब गपरा का एक दिन का रिमांड मिलत है।

100 जेलकर्मियों के पीएफ अकाउंट में की संधमारी

केंद्रीय जेल भेरवगढ़ के 100 कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में संधमारी हुई। जेल अकाउंटेंट द्वारा अपने दो जेल प्रहरी सचिवों के साथ पिछले 5 साल से जेल कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। खास बात ये है कि न तो पीडियों ने पीएफ निकालने के लिए आवेदन किया, न ही दरखास्त किए, फिर भी उनके पीएफ अकाउंट से पैसों निकाल गए। ट्रेजरी के अफसर के अफसर ने इस गबन को पकड़ा, जिसके बाद से मामले में चौकन्ने वाले खुलासे हो रहे हैं।

थाने से बंदूकें लूटने वालों को छुड़ा ले गए अतिक्रमणकारी

एक दिन पहले ही पकड़ाए थे; हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल

● **डिटैक्टिव ग्रुप रिपोर्ट**

बुरहानपुर। बुरहानपुरके नेगानगर में दो रात अतिक्रमणकारियों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। करीब 60 अतिक्रमणकारियों ने हमला कर आरोपी सचिन शर्मा को मेरवाण और अन्य से को पुलिस ने एक दिन पहले ही पकड़ा था। डीएम को गुरुवार रात बुरहानपुर में भीड़बा

पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तीनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।

बाकड़ों पर चौकी से बंदूकें लूटने वाले आरोपी सचिन शर्मा को मेरवाण और अन्य से को पुलिस ने एक दिन पहले ही पकड़ा था। डीएम को गुरुवार रात बुरहानपुर में भीड़बा

के सामने पेश कर पुलिस ने नेगानगर थाने में रखा था। अतिक्रमणकारियों ने एसएसआई गुलाब सिंह, अथवा मालवीय और एक अन्य पुलिसकर्मी से मदद मांगी। पुलिस थाने में तोड़फोड़ भी की है। हमले के बाद पुलिस ने नगर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।

● **थाने में रात में थे चार पुलिसकर्मी**

एस्पी राहुल कुमार लोहरे ने बताया कि रात में थाने में चार लोग थे। करीब 60 लोगों ने हमला किया। उनके चार सैनिकों में से दो मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर इलाका आत्मसंरक्षण करने वाले अतिक्रमणकारियों में से दो ही उठा पाए सतत कार्रवाई की जायेगी। बल डेमा को पकड़ा जा। इसके अलावा मरण पेटेल और नवाजी पटेल था। जल्द हमलाकारों के खिलाफ एक्शन लेंगे।

सावधान! आप भी तो नहीं बन रहे

फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का शिकार

मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने कुवैत के सुवर्ण को शादी का झांसा देकर लाखों

ऐसे चलता है ठगी का धंधा

एक सफल शादी के लिए नए नए ऑनलाइन वेबसाइट्स का उपयोग किया है, जो दुनिया भर में लोगों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये का धंधा चला रही हैं। फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का उपयोग करके लोगों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये का धंधा चलाया जा रहा है।



DETECTIVE GROUP
Detecting the truth

SAAT JANMO KA BANDHAN YA JHUT FAREB KI ULJHAN

PATA KARE SACH, DETECTIVE KE SANG

आज ही अपनी जानकारी सबमिट करे www.detectivegroup.in पर
Whatsapp us on [+91-91110 50101](https://www.whatsapp.com/channel/00291a111050101)

सीएम ने मुरैना एसपी आशुतोष बागरी को हटाया

मुख्यमंत्री को मिली शिकायतों के बाद जारी किए निर्देश

इंदौर में सीएम ने मुख्यमंत्री को लक्षित करके हटाया। सीएम शिवराज सिंह शेरवत ने मुरैना एसपी आशुतोष बागरी को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे, सीएम शेरवत को मुरैना एसपी को हटाने का आदेश मिला है।

इंदौर में बच्चों को पढ़ाने पहुंच रहे थे बागरी

बचपन से ही शिक्षण के प्रति उत्सुक बागरी ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ही एक कक्षा खोली।

इंदौर में बच्चों को पढ़ाने पहुंच रहे थे बागरी। बचपन से ही शिक्षण के प्रति उत्सुक बागरी ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ही एक कक्षा खोली।

मुरैना एसपी के पिता हुए थे सरपंच

जब मुरैना एसपी के पिता हुए इस योजना का लाभ प्राप्त करने की जानकारी मिली तो फैसला भी उठाया गया।

आशुतोष बागरी के पिता हुए इस योजना का लाभ प्राप्त करने की जानकारी मिली तो फैसला भी उठाया गया।

प्रशासन ने जांच की थी

जब पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के पिता का नाम मुरैना एसपी तौर पर दर्ज किया गया।

कमलनाथ बोले- ये देशभर में दंगे-फसाद करा रहे

शिवराज का पलटवार- डर दिखाओ, बोट पाओ; नरोत्तम ने कहा- जहर उलाना इनकी परंपरा

इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिद्रवादी में रोजा उभारना पार्टी में शामिल हुए। इसी दौरान का उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वे कह रहे हैं- आप सबका छिद्रवादी समझना है।

प्रबलना नरेंद्र सलुजा ने भी इसका बोका है। सलुजा ने यह वीडियो ट्विटर पर कहा- इन्होंने हमें रोकेगा तो बक रहे हैं कि आप आगेको छिद्रवादी समझना है।

शिवराज बोले- माइ इस समय शांति का टापू

कमलनाथ के बकाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शेरवत ने कहा, इसने अपनी छिद्रवादी जहर फैला दी है। एक राज्य में इतना बकना होना ही क्या करवाता है।

वे बदनीयता है, कुटिलता है, गुटकर्मण्य कर कमलनाथ को बोट फालिस करवा रहे हैं। इसकी निंदा करता हूँ।

नरोत्तम ने कहा- कांग्रेस को एक नहीं रख सके, देश को रहने दें

गुमनामी नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रोकेगाओं के बीच फैलकर विश्व ध्वस्त कराने, भय, अज्ञान पैदा करने, वे कांग्रेस को परंपरा पूरी बनाने जा रहे हैं।

जीजा को घेरकर गोली मारी, फिर गले में सब्बल घोंपी

एक घंटे सड़क पर पड़ा रहा शव

राजगढ़। राजगढ़ में अर्ध शक्ति का मजदूर मारपीत हुआ है। यहां एक युवक को पाले दो गोली मारी फिर गले में सब्बल घोंपकर हत्या कर दी।

गोली मारी फिर हत्या करने के बाद पाले में अक्षय प्रकाश मारी। लोहा अपने घोंपे के अंदर चला गया।

पटना जिले के भांगसूर बाजार क्षेत्र के शानोदा गंगे की है। यहां शुक्रवार रात 7:30 बजे एक सड़क दुर्घटना (26) घंटे के बस स्टैंड के पास रोडवर्क मजदूर के मजदूर के सड़क दुर्घटना-उत्पत्ति से मृत्यू का कारण बन रहा था।

मृतक लखन को बहन सजना ने बताया कि उसके भाई लखन का नाम की नौरू कुमर (26 वर्ष) से प्रेम प्रसंग था।

बीधीए के तत्कालीन इंजीनियर और ठेकेदार को तीन साल की सजा

भोपाल। कोट्टे ने भ्रष्टाचार के मामले में भोपाल विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री

भोपाल। कोट्टे ने भ्रष्टाचार के मामले में भोपाल विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री मुकेश खान और ठेकेदार अशोक कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है।

महाकाल मंदिर के नदी हॉल में जबरन घुसे नरोत्तम समर्थक

दरना करने पहुंचे थे गुहमंत्री, जमकर हंगामा

इंदौर में मुख्यमंत्री को लक्षित करके हटाया। सीएम शिवराज सिंह शेरवत ने मुरैना एसपी आशुतोष बागरी को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

और मंदिर के सूर्यकर्मियों ने उन्हें रोके। यह भी बताया गया, लेकिन वे जबरन घुसकर चले जा रहे थे।

कार्यकर्ताओं को गर्महू के सामने से हटवाया

महाकाल मंदिर के प्रशासक सीधे को और सड़क प्रशासक संतोषा चौहान ने मोर्चा समझाया और दृष्ट संतोष को पकड़कर बाहर भिजा।

समूह बनी रहे। यहाँ प्रार्थना की थी। गुहमंत्रियों ने महाकाल मंदिर के नदी हॉल में घुसकर प्रार्थना की।

सीधे सारे पंडित प्रसाद मिश्रा के स्टाम मजदूरों ने अज्ञानपूर्वक से अज्ञान अज्ञान विद्वानों के अज्ञान में अज्ञानी कथा की व्यवस्था की जमाना सारे हॉल में ले रहे थी।

संपादकीय

अभिव्यक्ति पर पहरा

सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आगामी दो टेम्पलैट करतें हुए केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई दावों के जटिल मीडिया पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। दूरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब डेढ़ साल पहले एक मलयालम टीवी चैनल का नवीकरण यह कहते हुए रोक दिया था कि उसका संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। केवल उच्च न्यायालय ने भी केंद्र के उस फैसले को उचित ठहराया था। तब चैनल के प्रबंधकों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई थी और उसने फैसला आने तक चैनल को अपना प्रसारण जारी रखने की इजाजत दे दी थी। अब उस मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी चैनल का नवीकरण न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। किसी चैनल या मीडिया संस्थान पर इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती कि वह सत्ता के विरोध में विचार प्रकाशित-प्रसारित करता है। सरकार की आलोचना राज्य की आलोचना नहीं होती। सरकार की नीतियों के खिलाफ विचार प्रकट करना मीडिया का धर्म है और इसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अगर सरकार इसलिए किसी चैनल पर प्रतिबंध लगा देती है कि वह उसके विरोध में विचार प्रकट करता है, तो इससे यह ध्वनिगत होता है कि सरकार केवल उन्हीं संचार माध्यमों को चलने देना चाहती है, जो उसके पक्ष में खबरें या वैचारिक सामग्री परोसते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उच्च न्यायालय को भी आड़े हाथों लिया और बंद लिफाफे में सरकार की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों पर एतदान जताया। गौरतलब है कि बंद लिफाफे में सुझाव या साक्ष्य पेश करने पर सर्वोच्च न्यायालय कई मौकों पर तल्ल टिप्पणी कर चुका है और उसकी स्पष्ट राय है कि कोई भी दस्तावेज गोपनीय तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए, उसे सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आने देना चाहिए। फिर संबंधित चैनल पर यह भी आरोप था कि उसके मालिकों से भी अधिकतर का संबंध जनात-ए-इस्लामी-हिंद से है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इससे मीडिया के अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक ही, अदालत के इस फैसले से अभिव्यक्ति की आगामी को लेकर एक और जनता कायम हुई है। यह ठीक है कि मीडिया की आगामी का हमारे संविधान में उस तरह स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिस तरह अमेरिका आदि लोकतांत्रिक देशों में है, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रहते मीडिया को यह अधिकार मिला हुआ है। इस तरह के फैसले से मीडिया की स्वतंत्रता टेम्पलैट हुई है और उसे लोकतंत्र के चौरे दस्तक के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। अगर सरकारें अक्सर मीडिया की लिखावट और सरकारों नीतियों, फैसलों के चिह्नक मुद्रता से असहज महसूस करती देखी जाती हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाती रही हैं। ऐसे असहजों और समाचार चैनलों के हिस्से का विनाशपूर्ण जंका सरकारों का आसान हथकंडा है, जो उसके खिलाफ लिखते-बोलते हैं। इसे लेकर भी कुछ अखबारों ने कुछ साल पहले सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तब भी अदालत ने सरकारों को ऐसी ही कड़ी फटकार लगाई थी। पिछले कुछ सालों से मीडिया की भूमिका को लेकर निरंतर प्रकट की जाती रही है।

महिला जगत

शहीद मेजर की बेटी ने संभाली परिवार की विरासत, ऐसे कर रही पिता के सपने को पूरा



देश की रक्षा के लिए सौभाग्य से पर तैनात सैनिक न तो अपने परिवार को और न ही जान को परवाह नहीं करते। सैनिक जिनसे मासूम होते हैं, उनका परिवार उससे अधिक प्रभावित होता है। किसी के पिता, तो किसी के पति देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। ऐसी ही एक बेटी ने अपने पिता को आत्मकवार्द विरोधी अभियान में खो दिया लेकिन उस बेटी ने अपने पिता के नवोदय पर चलने की ठान ली और खुद भी सेना में शामिल हो गईं। आज यह बेटी इस परिवार की सीमाती है, जो देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल हैं। देश की इस बेटी का नाम इनाम बख्त है। आखर जानते हैं इनाम बख्त की कहानी।

शहीद मेजर की बेटी हैं इनाम बख्त

इनाम बख्त हरियाणा के पंचकुला में रहने वाली हैं। इनाम अपने जन्म पिता के इस्लामी बेटी हैं। इनाम के पिता का नाम नवलत बख्त है जो कि सेना में मेजर के पद पर कार्यरत थे। जब इनाम मात्र बस बड़े बालक थीं, तब 2003 में मेजर नवलत बख्त ने जम्मू कश्मीर के एक आत्मकवार्द विरोधी अभियान में जान गंवा दी थी। इनाम बख्त के पिता को मर्यादागत सेना परक से आत्मकवार्द विरोधी युद्ध है। इनाम के नाम भी पौरव में बनने लगे।

दाई साल की उम्र में इनाम ने पिता को खोया

20 साल पहले अपने पिता को खो चुकी इनाम ने अपने पिता को क्रिसमस को जारी रखने का फैसला लिया और भारतीय सेना में शामिल हो गईं।

अलेक में इनाम चेवर्ह में रिजल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में शामिल होने वाली हैं।

इनाम बख्त की शिक्षा

इनाम बख्त ने दिल्ली के लेडी ग्रैमर कॉलेज से स्नातक किया और बाद में डीए के हिंदू कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया। इनाम को शहीदों के परिवारों के लिए राज्य की नीति के तहत राजकीय पद पर नियुक्ति मिल सकती है, लेकिन उन्हें पिता की तरह ही सेना में भर्ती होना है। इनाम को भी और उनके परिवार ने भी इस फैसले में उनका साथ दिया।

शहीद मेजर नवलत बख्त और शिवानी की शहीद को खबर पार साल हुए से जब वह शहीद हो गए थे। शिवानी उस समय सिर्फ 27 साल की थीं। उसके बाद वह चंडीगढ़ में एक अर्द्ध-पब्लिक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर कार्य करने लगीं।

Highlights

- 1. Narayana Murthy's son shares pics of his parents receiving Padma award 15 years apart**
- 2. Israel launches attack on Hamas after more than 30 rockets fired at the country**
- 3. Enemies will pay price: Netanyahu after Lebanon rockets hit Israel**
- 4. Indian man awarded ₹11 crore over bus crash which left him critically injured in Dubai**
- 5. Byju's lenders seek \$200-mn prepayment to restructure loan: Report**
- 6. Cabinet approves Indian Space Policy, 2023**
- 7. Govt hospital's physiotherapist arrested for taking bribe in Pune**
- 8. Car hits divider, rams into truck on Pune-Mumbai highway; 4 dead**

RBI proposes expansion of UPI digital payments system to allow credit

NEW DELHI, (Agency). In RBI's industrial outlook survey, the cost of raw materials is no longer as big a drag. Within the services outlook survey, selling prices have risen and profit margins have widened after shrinking for a few quarters (MINT)

"This initiative will further encourage innovation," RBI governor Shaktikanta Das said on Thursday during the announcement of the central bank's monetary policy decision.

UPI is an instant real-time payments system that allows users to transfer money across multiple banks without disclosing bank account details. Its popularity is seen to have reduced the usage of cash and debit cards for daily transactions.

In March 2023, UPI recorded 8.65 billion transactions, amounting to 14.05 trillion



rupees, its highest-ever since inception, data from the National Payments Corporation of India showed.

In a bid to boost digital payments, the RBI recently allowed RuPay credit cards to be linked to UPI. This was to enable customers to link their credit cards and pay via UPI.

By allowing banks to offer customers a pre-approved credit line, UPI accounts could now offer an alternative to credit cards, said Srinath

Sridharan, an independent policy researcher. "It could change the way banks look at credit cards."

Commenting on India's digital infrastructure, the IMF said on Thursday, "Using this digital infrastructure India was able to quickly provide support to an impressive share of poor households during the pandemic. In the first months of the pandemic about 87 per cent of poor households received at least one benefit."

Google and Amazon struggle to lay off workers in Europe. Here's why

NEW DELHI, (Agency). After announcing the largest rounds of layoffs in their history, US big tech companies are now learning how difficult it is to reduce headcount in Europe.

In the US, companies can announce widespread job cuts and let go of hundreds if not thousands of workers within months – and many have. Meanwhile, in Europe, mass layoffs among tech companies have stalled because of labour protections that make it virtually impossible to dismiss people in some countries without prior consultations with employee interest groups.

This has left thousands of tech workers in limbo, unsure about whether they'll be affected by negotiations that can drag on indefinitely.

In France, Google parent



Alphabet Inc. is currently in talks to reduce headcount through voluntary departures, offering severance packages that it hopes are generous enough to get workers to leave, people familiar with the matter said, asking not to be identified because the information isn't public. Amazon has tried to get some senior managers there to resign by dangling as much as one year's pay and has granted leave to departing employ-

ees so their shares can vest and be paid out as bonuses, one person with knowledge of the situation said.

Both in France and Germany, where labour laws are among the strongest in the EU, Google is currently in negotiations with works councils – company-specific groups whose elected employee representatives negotiate with management about workforce issues, according to a person familiar with the matter.

